



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941

No. 372]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 22 अक्टूबर, 2019

सं. टीएएमपी/26/2019-सीआईटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा चेन्नई इंटरनैशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) से प्राप्त सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) निर्यात कंटेनरों के निशुल्क दिवसों में वृद्धि को उनके दरमानों में अंतर्विष्ट करने के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/26/2019-सीआईटीपीएल

चेन्नई इंटरनैशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

—

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर 2019 के 10वें दिन पारित)

मामला चेन्नई इंटरनैशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) से प्राप्त सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) निर्यात कंटेनरों के निशुल्क दिवसों में वृद्धि को उनके दरमानों में अंतर्विष्ट करने के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. सीआईटीपीएल के दरमानों का पिछला संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा 6 जनवरी 2012 के आदेश संख्या टीएएमपी/51/2011-सीआईटीपीएल द्वारा किया गया था जिसमें तत्समय प्रचलित प्रशुल्क पर (यानी 3 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल में अनुमोदित) *अक्रास दा बोर्ड* 12.23% घटौती प्रभावित की गई थी। सीआईटीपीएल ने अपनी रिट याचिका संख्या 2012 के 11010 और 11011 के द्वारा 6 जनवरी 2012 के प्रशुल्क आदेश को माननीय मद्रास

उच्च न्यायालय से संपर्क किया। माननीय उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी, 2012 के आदेश पर रोक लगा दी और सीआईटीपीएल को 3 नवंबर, 2010 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार अनुमोदित प्रशुल्क की उगाही जारी रखने की अनुमति दे दी।

2.2. इस पृष्ठभूमि में, सीआईटीपीएल अब 03 नवंबर, 2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल द्वारा यथाअनुमोदित सीआईटीपीएल के दरमानों के खंड 3.11 में निर्धारित भंडारण अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव के साथ आया है।

3.1. सीआईटीपीएल ने 21 मई 2019 के प्रस्ताव पत्र संख्या सीआईटीपीएल/जीईएन/ओपीएस/649 के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये हैं:

- (i). विश्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध "व्यापार करने की सुगमता" की रैंकिंग में भारत के रैंक में सुधार लाने के लिए भारतीय पत्तनों ने काफी कदम उठाये हैं। लागू की गई स्कीमों में से एक सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) है।
- (ii). सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के (07.09.2016) परिपत्र संख्या एफ 450/2009- सीमा शुल्क-IV के द्वारा लागू की गई एक नई स्कीम है। यह स्कीम एक व्यापार सुविधा पहल है जिसके अंतर्गत निर्यात कंटेनरों का पत्तन में सीधे प्रवेश की अनुमति देने से निर्यात कंटेनरों के फैक्ट्री से पोत पर आन-बोर्ड लदान के ठहराव समय को कम करना तथा पत्तन में ही एलईओ (निर्यात आदेश देना) की मंजूरी दी जाती है।
- (iii). सीबीईसी ने उन डीपीई कंटेनरों के लिए 5 निशुल्क दिवस बढ़ा दिये हैं जो अधिकतर डीपीई ग्राहकों को अपने कंटेनरों को निजी पत्तनों पर ले जाने को प्रभावित करते हैं।
- (iv). सीआईटीपीएल के अनुसार वर्तमान दरमानों के खंड 3.11, के अनुसार निर्यात कंटेनर भंडारण की 07 दिन की निशुल्क अवधि के पात्र हैं। इस प्रकार, सीआईटीपीएल ने डीपीई ग्राहकों के लिए निशुल्क अवधि को वर्तमान 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव किया है।

3.2. सीआईटीपीएल का प्रस्ताव अपने दरमानों के भाग 3.11 के भंडारण अनुसूची में क्रमांक 2(क) के रूप में नई प्रविष्टि करने का है। वर्तमान और भंडारण अनुसूची की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

(क). वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	विवरण	विदेशगामी पोत			तटीय पोत		
		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (अमरीकी डॉलर में)			दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (रु.में)		
2	निर्यात- एफसीएल, एलसीएल एवं खाली	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	8-15 दिन	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00

(ख). प्रस्तावित उपबंध:

क्र.सं.	विवरण	विदेशगामी पोत			तटीय पोत		
		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (अमरीकी डॉलर में)			दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (रु.में)		
2	निर्यात- एफसीएल, एलसीएल एवं खाली	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क

	8-15 दिन	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2(क)	डीपीई- एफसीएल	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-15 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	लागू नहीं		
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00			
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00			

4.1. सीआईटीपीएल द्वारा किये गये अनुरोध को हमारे 24 मई, 2019 के पत्र के द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन यानी चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया।

4.2. प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने 03 जून 2019 के ई-मेल द्वारा निम्नलिखित संसूचना दी:

- (i). पिछले कुछ वर्षों में, चेन्नई पत्तन के दोनों टर्मिनलों में निर्यात कंटेनरों की वृद्धि कट्टुप्पलयांड, कृष्णापत्तनम आदि पत्तनों से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुई है क्योंकि ये पत्तन चेन्नई पत्तन में प्रचालित पोतों ने अपनी सीएचईएक्स सेवाओं को चेन्नई से कट्टुप्पल्ली टर्मिनल और केपीएल को स्थानांतरित कर लिया है और चेन्नई पत्तन न्यास (सीआईटीपीएल) से प्रचालित एसीएस सेवा को कट्टुप्पल्ली टर्मिनल को परिवर्तित कर दिया है।
- (ii). अन्य पत्तनों में निजी कंटेनर टर्मिनल प्रचालक पोत संबंधी प्रभावों में भारी छूट और निशुल्क पार्किंग स्थान, डीपीई कंटेनरों के लिए अधिक भंडारण अवधि आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देकर करते हैं। निर्यात कंटेनर इन अतिरिक्त सुविधाओं की ओर सुगमता से आकर्षित हो जाते हैं मुख्यतः कट्टुप्पल्ली और कामराज पत्तन कंटेनर टर्मिनल पर सुगम पहुंच होती है और चूंकि यह पत्तन उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां सड़के भीड़-भाड़ वाली नहीं हैं शहरी यातायात से दूर है।
- (iii). इस प्रवृत्ति को रोकने के उपाय के एक भाग के रूप में, टर्मिनलों ने निर्यात कंटेनरों के भंडारण की निशुल्क अवधि को 7 से 15 तक बढ़ा दिया जाए। वे महसूस करते हैं कि इससे कुछेक निर्यातक कंटेनरों को पहले ही मूव कर पायेंगे और पोत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए वे समय पर चेन्नई टर्मिनल पहुंच पायें।
- (iv). इस समय, वे ऐसा कदम उठाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि चेन्नई टर्मिनल 7 दिन की निशुल्क अवधि से बंधे है जबकि निजी कंटेनर टर्मिनल चुनिंदा निर्यात ग्राहकों को 14-30 दिन की निशुल्क अवधि प्रदान करते हैं।
- (v). उपरोक्त को देखते हुए, सीआईटीपीएल के प्रस्ताव को व्यापार के हित को ध्यान में रखकर स्वीकार कर लिया जाए।

5.1. सीएचपीटी से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, सीआईटीपीएल को तदर्थ आधार पर अनुमोदन संसूचित करते हुए 03 जून, 2019 को पत्र संख्या टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल जारी किया गया था कि वह अपने दरमानों के खंड 3.11 (कंटेनर भंडारण प्रभार) में क्रमांक 2(क) अंतर्विष्ट कर ले, जैसा ऊपर पैरा 3.2(ख) में चर्चा की गई है। सीआईटीपीएल को यह भी संसूचित किया गया है कि तदर्थ अनुमोदन इस प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई परामर्श प्रक्रिया के परिणामों के अधीन होगा। 03 जून 2019 के उक्त पत्र के द्वारा सीएचपीटी और सीआईटीपीएल को यह निर्देश भी दिया गया कि नई प्रशुल्क प्रविष्टि के कार्यान्वयन की तारीख भी बतायी जाये।

5.2. इस संबंध में, सीआईटीपीएल ने 11 जुलाई 2019 के ई-मेल द्वारा यह संसूचित किया कि डीपीटी निर्यात कंटेनरों के लिए 15 दिन की निशुल्क भंडारण अवधि सीआईटीपीएल में 21 जून, 2019 से प्रभावी की गई है।

6. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीआईटीपीएल के 21 मई, 2019 के प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को हमारे 10 जुलाई, 2019 के पत्र के द्वारा उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई। किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने मामले की अंतिमता तक कोई टिप्पणी नहीं दी।

7. संदर्भित मामले में चेन्नई में सीएचपीटी परिसर में 2 अगस्त, 2019 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी तथा प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

8. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आई:

- (i). चेन्नई इंटरनैशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) के मौजूदा दरमानों के अनुसार, सभी प्रकार के निर्यात कंटेनरों के लिए 7 दिन की निशुल्क अवधि मिलती है। सीआईटीपीएल ने बताया है कि सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) कंटेनरों के प्रहस्तन की क्रियाओं के अनुसार निर्यातकों के टर्मिनल परिसर में कंटेनर जमा करके रखने पड़ते हैं। चूंकि निर्यातकों को इस मद पर निशुल्क दिवसों की समाप्ति के पश्चात् अतिरिक्त भंडारण प्रभार देने पड़ते हैं, इसलिए वे अपने कार्गो के निर्यात के लिए सीआईटीपीएल के प्रयोग से हिचकिचाते हैं क्योंकि अन्य छोटे टर्मिनल ज्यादा निशुल्क अवधि प्रदान करते हैं। इस प्रकार, डीपीटी ग्राहकों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से, सीआईटीपीएल डीपीई ग्राहकों के लिए 7 दिन की मौजूदा निशुल्क अवधि को बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव लेकर आया है। यह बताया गया है कि प्रस्ताव डीपीई ग्राहकों के अनुरोध पर आधारित है।
- (ii). जैसा आदेश के पहले भाग में चर्चा की गई है, सीआईटीपीएल के संबंध में 6 जनवरी, 2012 के पिछले प्रशुल्क आदेश पर माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। माननीय न्यायालय ने 03 नवंबर, 2010 के यथाअनुमोदित प्रशुल्क आदेश के अनुसार उगाही करने की अनुमति दी है। सीआईटीपीएल यथाप्रस्तावित निशुल्क अवधि में वृद्धि 03 नवंबर, 2010 के आदेश में यथाअनुमोदित दरमानों के संदर्भ में है।
- (iii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों का खंड 9.10.1 (जो सीआईटीपीएल के मामले में संगत है) व्यक्ति वीओटी प्रचालक को निशुल्क दिवस का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है। तदनुसार, डीपीई कंटेनरों के लिए निशुल्क दिवसों में वृद्धि चाहने का सीआईटीपीएल का प्रस्ताव प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में दी गई अनुबद्धताओं के भीतर पाया जाता है।
- (iv). लाइसेंस प्रदाता पत्तन, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी), ने सीआईटीपीएल के प्रस्ताव का समर्थन किया है और प्रयोक्ताओं ने भी सीआईटीपीएल के प्रस्ताव का अपना पूरा समर्थन दिया है।
- (v). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर और सीएचपीटी तथा प्रयोक्ता संगठनों द्वारा दिये गए समर्थन को देखते हुए यह प्राधिकरण सीआईटीपीएल के मौजूदा निशुल्क 7 दिनों को डीपीई कंटेनरों के लिए बढ़ाकर 15 दिन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।
- (vi). सीएचपीटी से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सीआईटीपीएल को तदर्थ आधार पर निशुल्क दिनों में वृद्धि करने की अनुमति पहले ही दे दी गई है जो इस प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई परामर्शी कार्यवाही के परिणामों पर निर्भर करेगी। सीआईटीपीएल के प्रस्ताव पर न तो सीएचपीटी और न ही प्रयोक्ताओं को कोई आपत्ति है। सीआईटीपीएल ने संसूचित किया है कि डीपीई निर्यात कंटेनरों के लिए सीआईटीपीएल में 15 दिन का निशुल्क भंडारण 21 जून 2019 से कार्यान्वित कर दिया गया है। अतः डीपीटी निर्यात कंटेनरों के लिए निशुल्क दिनों की वृद्धि 21 जून 2019 से प्रभावी मानी जायेगी और तब तक वैध रहेगी जब तक

प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर सीआईटीपीएल के दरमानों की समीक्षा नहीं की जाती।

10.1. परिणाम में, और ऊपर बताये गए कारणों के लिए तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीआईटीपीएल के दरमानों के भाग 3.11 के क्रमांक 2 की मौजूदा अनुसूची को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन देता है:-

“

क्र.सं.	विवरण	विदेशगामी पोत			तटीय पोत		
		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (अमरीकी डॉलर में)			दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग (रु.में)		
2	निर्यात- एफसीएल, एलसीएल एवं खाली	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	8-15 दिन	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2(क)	डीपीई- एफसीएल	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक	20' तक	20'से अधिक और 40' तक	40'से अधिक
	0-15 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	लागू नहीं		
	16-30 दिन	11.00	22.00	33.00			
	30 दिन से आगे	22.00	44.00	66.00			

”

10.2 सीआईटीपीएल को सलाह दी जाती है कि वह 3 नवम्बर, 2010 के प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित अपने दरमानों में उपयुक्त संशोधन करें।

10.3. डीपीटी निर्यात कंटेनरों के लिए निशुल्क दिनों की वृद्धि 21 जून 2019 से प्रभावी मानी जायेगी और तब तक वैध रहेगी जब तक प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर सीआईटीपीएल के दरमानों की समीक्षा नहीं की जाती।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन -III/4/असा./255/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd October, 2019

No. TAMP/26/2019-CITPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai International Terminal Private Limited (CITPL) for increasing the free days for Direct Port Entry (DPE) Export containers in its Scale of Rates, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/26/2019-CITPL

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 10th day of October 2019)

This case relates to a proposal received from Chennai International Terminal Private Limited (CITPL) for increasing the free days for Direct Port Entry (DPE) Export containers in its Scale of Rates.

2.1. The Scale of Rates of CITPL was last revised by this Authority vide Order No. TAMP/51/2011-CITPL dated 6 January 2012, wherein an across the board reduction of 12.23% was effected over the then prevailing tariff (i.e. tariff approved vide Order No. TAMP/10/2009-CITPL dated 3 November 2010). The CITPL has approached the Hon'ble High Court of Madras challenging the tariff order dated 6 January 2012 by its Writ Petition No. 11010 and 11011 of 2012. The Hon'ble High Court has stayed the tariff Order dated 6 January 2012 and has allowed the CITPL to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 3 November 2010.

2.2. In this backdrop, the CITPL has now come up with a proposal proposing amendment in the storage schedule prescribed at Section 3.11 in the CITPL Scale of Rates as approved vide the tariff Order No. TAMP/10/2009-CITPL dated 03 November 2010.

3.1. The submissions made by CITPL vide its letter no. CITPL/GEN/OPS/649 dated 21 May 2019 are as follows:

- (i). With a view to improve India's rank on "Ease of Doing Business" rankings listed out by World Bank. Indian ports have taken a series of steps. One of the scheme introduced is Direct Port Entry (DPE).
- (ii). Direct Port Entry (DPE) is new scheme introduced by Central Board of Indirect Taxes & Customs vide circular F.No. 450/2009-Cus IV dated (07.09.2016). This scheme is a trade facilitation initiation to reduce the dwell of export container from factory to onboard the vessels by directly allowing the entry of export containers into the ports and granting of (Let export order) LEO in the port itself.
- (iii). CBEC has extended 5 days free days for DPE customers which influence majority of DPE customers diverting their containers through such private Ports.
- (iv). As per CITPL existing scale of rates (SOR) at clause 3.11, export containers are eligible for 07 days free storage period. Thus, the CITPL proposes to increase the free period for the DPE customers from the existing 7 days to 15 days.

3.2. The proposal of the CITPL is to introduce a new entry in the storage schedule as Sl no. 2(a) at Section 3.11 of its Scale of Rates. A comparative position of the existing and the proposed storage schedule is given below:

(a). Existing provision

Sr. No	Particulars	Foreign going Vessels			Coastal Vessels		
		Rate per container per day Or part thereof (in US\$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
2	Export – FCL, LCL & Empty	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	8-15 days	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00

(b). Proposed provision:

Sr. No	Particulars	Foreign going Vessels			Coastal Vessels		
		Rate per container per day Or part thereof (in US\$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
2	Export – FCL, LCL & Empty	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	8-15 days	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00

	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2(a)	DPE-FCL	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-15 days	Free	Free	Free	Not Applicable		
	16-30 days	11.00	22.00	33.00			
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00			

4.1. The request made by CITPL was forwarded vide our letter dated 24 May 2019 to the Licensor Port i.e., Chennai Port Trust (CHPT), seeking its comments.

4.2. In response, the CHPT vide its e-mail dated 03 June 2019 has conveyed the following:

- (i). In the last couple of years, the growth of the export containers in the two Terminals in Chennai Port has been affected with increased competition from Kattuppalli and Krishnapatnam ports attracting lines operating in Chennai Port; Vessel operators like Maersk have shifted its CHEX service from Chennai to Kattuppalli Terminal and KPL and part of volumes from ACS service operating from Chennai Port Trust (CITPL) has been diverted to Kattuppalli Terminal.
- (ii). The Private Container Terminal Operators in other ports do this by giving considerable discount in Vessel Related Charges and additional facilities like free parking space, increased storage period for DPE containers etc., Export containers are easily attracted to these additional facilities mainly because of the easy access to Kattuppalli and Kamarajar Port Container Terminal since these ports are located in areas where roads are less congested and are away from City traffic.
- (iii). As part of the measures to arrest this trend, the terminals have proposed to increase the free period of storage of export containers from 7 to 15 days. They feel that this will enable some of the exporters to move the containers in advance and reach the terminals in Chennai in time to ensure vessel connectivity.
- (iv). At present they are not able to resort to this measure because of the restricted free period of 7 days in Chennai Terminals whereas neighbouring private container terminals are providing 14-30 days free storage period for select Export customers.
- (v). In view of the above, the proposal of CITPL, may be agreed to considering the interest of the Trade.

5.1. Based on the comments received from the CHPT, a letter no. TAMP/10/2009-CITPL dated 03 June 2019 was issued to CITPL conveying adhoc approval to CITPL to insert Sr. No. 2(a) in Section 3.11 (Charges for Container Storage) of its Scale of Rates as brought out at Para no. 3.2 (b) above. It was also conveyed to CITPL that the adhoc approval is subject to the outcome of the consultation proceedings to be initiated by this Authority. Vide the above said letter dated 03 June 2019, the CHPT and CITPL were also directed to indicate the date of implementation of the new tariff entry.

5.2. In this regard, the CITPL vide its e-mail dated 11 July 2019 has conveyed that the free storage of 15 days for DPE export containers has been implemented at CITPL with effect from 21 June 2019.

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CITPL proposal dated 21 May 2019 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide letter dated 10 July 2019 seeking their comments. None of the users/ user organizations have given their comments till the case was finalized.

7. A joint hearing on the case in reference was held on 2 August 2019 in the premises of the CHPT at Chennai. At the joint hearing, CITPL and users/ user organisation have made their submissions.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). As per the existing Scale of Rates of the Chennai International Terminal Private Limited (CITPL), all types of Export containers enjoy a free period of 7 days. The CITPL has stated that as per the modalities of handling of Direct Port Entry (DPE) Containers, it requires the exporters to accumulate and hold the containers at the terminal premises. Since the exporters incur additional storage charges after expiry of free days on this account, there is reluctance on the part of exporters to use CITPL for export of their cargo, as other non-major ports give more number of free days. Thus, inorder to facilitate DPE customers, the CITPL has come up with a proposal seeking an increase in the free days

from the existing 7 days to 15 days, in respect of the DPE customers. The proposal is reported to be based on the request made by the DPE customers.

- (ii). As brought out in the earlier part of the Order, the last tariff Order dated 6 January 2012 in respect of CITPL has been stayed by Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble Court has allowed the CITPL to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 3 November 2010. The increase in the free period as proposed by CITPL, is with regard to the Scale of Rates as approved vide Order dated 03 November 2010.
- (iii). Clause 9.10.1 of the Workings Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, (which is relevant incase of CITPL), allows the individual BOT operators to propose free days. Accordingly, the proposal of CITPL seeking an increase in the free days for the DPE containers, is seen to be within the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019.
- (iv). The Licensor port Chennai Port Trust (CHPT) has endorsed the proposal of the CITPL and the users have also extended their support to the proposal of the CITPL.
- (v). Based on the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019, and considering the support extended by the CHPT and the user organization, this Authority is inclined to approve the proposal of the CITPL to increase the free days for the DPE containers from the existing 7 days to 15 days.
- (vi). Based on the comments received from the CHPT, the CITPL has already been allowed to increase the free days on an adhoc basis, subject to the outcome of the consultation proceedings initiated by this Authority. There was no objection to the CITPL proposal either from the CHPT or from the user. The CITPL has conveyed that the free storage of 15 days for DPE export containers has been implemented at CITPL with effect from 21 June 2019. Thus, the provision relating to increase in the free days for DPE export containers is deemed to have come into effect from 21 June 2019 and shall remain valid till the Scale of Rates of CITPL is reviewed based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019.

10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval to replace the existing schedule at Sl. no. 2 at Section 3.11 of the CITPL Scale of Rates with the following:

“

Sr. No	Particulars	Foreign going Vessels			Coastal Vessels		
		Rate per container per day Or part thereof (in US\$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
2	Export – FCL, LCL & Empty	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	8-15 days	5.50	11.00	16.50	231.00	462.00	693.00
	16-30 days	11.00	22.00	33.00	462.00	924.00	1386.00
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00	924.00	1848.00	2772.00
2(a)	DPE-FCL	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'	Upto 20'	Above 20' and 40'	Above 40'
	0-15 days	Free	Free	Free	Not Applicable		
	16-30 days	11.00	22.00	33.00			
	Beyond 30 days	22.00	44.00	66.00			

”

10.2 The CITPL is advised to suitably amend the Scale of Rates approved in the tariff Order dated 3 November 2010.

10.3. The provision relating to increase in the free days for DPE export containers is deemed to have come into effect from 21 June 2019 and shall remain valid till the Scale of Rates of CITPL is reviewed based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./255/19]